nhrc.in

National Human Rights Commission in partnership with University of Manipur organized a 2-day ‘training programme on human rights in India’

https://nhrc.nic.in/media/press-release/national-human-rights-commission-partnership-university-manipur-organized-2-day-

Press Release

National Human Rights Commission

New Delhi, 30th August 2024

National Human Rights Commission in partnership with University of Manipur organized a 2-day ‘training programme on human rights in India’

More than 100 students, faculty members and jurists attended the programme and discussed various dimensions of human rights

Shri Bharat Lal, Secretary General in his valedictory address emphasized Constitutional values - equality, justice, liberty and fraternity

He appealed to students to consider rights and duties together, and bring a culture of non-violence and respecting human rights of fellow human beings

The University of Manipur, in collaboration with the National Human Rights Commission (NHRC), successfully concluded a ‘Two-Day Training Programme on Human Rights in India’ on 30th August 2024. The programme, hosted at the Court Hall, Manipur University, witnessed the participation of over 100 legal experts, academicians, Human Rights Defenders, and students.

The programme was concluded with the valedictory address delivered by Shri Bharat Lal, Secretary General of the NHRC. In his address, Shri Lal emphasized the importance of the true meaning of Preamble, Fundamental Rights, and Directive Principles of State Policy. He also spoke on constitutional and legal recourse available to citizens for securing justice, especially Article 32 in seeking justice. He reiterated the government's responsibility in upholding civil, political, cultural, and socio-economic rights.

Shri Lal stressed the need to foster fraternity among people as enshrined in the Constitution, urging reliance on constitutional and legal provisions rather than violence to achieve justice. He asserted that upholding Human Rights must be an internal commitment, not an externally imposed duty.

Shri Bharat Lal emphasized that the Preamble, the soul of the Constitution, encapsulates the core ideals of equality, justice, liberty, and fraternity. He asserted that any form of violence is fundamentally a violation of Human Rights, highlighting that war, terrorism, and violence are among the greatest threats to human life and dignity. In his

address, Shri Lal urged students and teachers alike to actively promote peace and respect for human rights of all human beings emphasizing that these efforts are essential for securing prosperity and a bright future for the younger generation.

He also highlighted the NHRC's recent camp sitting in Guwahati, where 25 cases of alleged Human Rights violations in Manipur were addressed. Shri Lal reaffirmed the NHRC's commitment to protecting and promoting Human Rights for all, calling for collective resolve and sustained efforts to ensure that respecting Human Rights becomes a way of life. He concluded by encouraging partnerships to improve lives and ensure dignity for everyone.

The programme featured eight key sessions addressing critical aspects of human rights. The event brought together over 100 participants, including legal experts, academicians, and Human Rights activists. On its first day, Prof. Rameshchandra Borpatragohain, former Dean, opened the sessions with an overview of Human Rights principles and practices, followed by Dr. N. Pramod Singh,Associate Professor Dhanamajuri University, who discussed the role of Human Rights institutions in India. Hon'ble Justice Kh. Nobin Singh explored the intersection of Human Rights and the Criminal Justice System, while Shri Keisham Pradipkumar, Hon'ble Chairperson MCPCR, addressed child rights challenges in Manipur. Mrs Sobita Mangsatabam, Secretary of Women Action for Development, highlighted the role of NGOs in gender justice, and Mr Meihoubam Rakesh, Director of Human Rights Law Network, Manipur, examined constitutional safeguards on arrest and detention. Mr. Rinku Khumukcham, Chief Editor of Imphal Times, discussed the role of media in promoting and protecting human rights.

This programme marks a significant step in advancing Human Rights education and advocacy in the North-East, with continued commitment from NHRC to fostering respect and understanding of Human Rights. NHRC continues to work with renewed vigour in partnership with Central and various state governments, their parastatal organizations, academic institutions, NGOs, human rights defenders, especially youth and women to protect and promote human rights and treating every human being with respect and dignity, as a way of life.

PIB

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 'भारत में मानवाधिकारों पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजित किया

इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्र, संकाय सदस्य एवं न्यायविदों ने हिस्सा लिया और मानवाधिकारों के विभिन्न आयामों पर चर्चा की

महासचिव श्री भरत लाल ने अपने समापन भाषण में संवैधानिक मूल्यों - समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर दिया

श्री लाल ने छात्रों से अधिकारों और कर्तव्यों पर एक साथ विचार करने, अहिंसा की संस्कृति लाने तथा साथी मनुष्यों के मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2050471

Posted On: 31 AUG 2024 5:19PM by PIB Delhi

मणिपुर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 30 अगस्त, 2024 को 'भारत में मानवाधिकारों पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम' सफलतापूर्वक संपन्न किया। मणिपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार रक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम का समापन एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल के भाषण के साथ हुआ। अपने संबोधन में श्री लाल ने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के सही अर्थ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी उपायों, विशेष रूप से न्याय प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32, पर भी बात की। श्री लाल ने नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बनाए रखने में सरकार की जिम्मेदारी को एक बार फिर दोहराया।

महासचिव महोदय ने संविधान में निहित लोगों के बीच बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसा के बजाय, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर भरोसा करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवाधिकारों का पालन एक आंतरिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि बाहरी रूप से थोपा गया कर्तव्य।

श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावना, जो कि संविधान की आत्मा है, इसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल आदर्श समाहित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा का कोई भी रूप मूल रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इस बात पर प्रकाश डाला कि युद्ध, आतंकवाद और हिंसा मानव जीवन एवं सम्मान के लिए सबसे बड़े खतरों में से हैं। अपने संबोधन में, श्री लाल ने छात्रों और शिक्षकों दोनों से सभी लोगों के मानवाधिकारों के लिए शांति एवं सम्मान को

सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि ये प्रयास युवा पीढ़ी के लिए समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।

उन्होंने गुवाहाटी में एनएचआरसी के हाल ही में आयोजित शिविर पर भी प्रकाश डाला, जहां मणिपुर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के 25 मामलों का समाधान किया गया। श्री लाल ने सभी के लिए मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की और यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक संकल्प और निरंतर प्रयासों का आह्वान किया, ताकि मानवाधिकारों का सम्मान करना जीवन का एक तरीका बन जाए। उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने और सभी के लिए सम्मान सुनिश्चित करने हेतु भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अपने भाषण का समापन किया।

इस कार्यक्रम में मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले आठ प्रमुख सत्र शामिल थे। इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन, पूर्व डीन प्रो. रमेशचंद्र बोरपात्रगोहेन ने मानवाधिकार सिद्धांतों और प्रथाओं के विहंगावलोकन के साथ सत्रों की शुरुआत की, उसके बाद धनमाजुरी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एन. प्रमोद सिंह ने भारत में मानवाधिकार संस्थानों की भूमिका पर चर्चा की। माननीय न्यायमूर्ति केएच नोबिन सिंह ने मानवाधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली के मध्य कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया, जबकि श्री कैशम प्रदीपकुमार, माननीय अध्यक्ष एमसीपीसीआर ने मणिपुर में बाल अधिकार संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। विमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट की सचिव श्रीमती सोबिता मंगसताबम ने लैंगिक न्याय में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला और मणिपुर के मानवाधिकार कानून नेटवर्क के निदेशक श्री मेइहोबाम राकेश ने गिरफ्तारी और नजरबंदी पर संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर विचार किया। इंफाल टाइम्स के मुख्य संपादक श्री रिंकू खुमुकचम ने मानवाधिकारों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की।

यह कार्यक्रम उत्तर-पूर्व में मानवाधिकार शिक्षा और इसकी हिमायत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मानवाधिकारों के सम्मान एवं समझ को बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी की निरंतर प्रतिबद्धता है। एनएचआरसी मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने तथा प्रत्येक मनुष्य के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने हेतु, जीवन के एक तरीके के रूप में, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों, उनके अर्ध-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, मानवाधिकार रक्षकों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के साथ भागीदारी में नए उत्साह के साथ काम करना जारी रखे हुए है।

The Print

Manipur: NHRC stresses on need to foster fraternity, eschew violence

https://theprint.in/india/manipur-nhrc-stresses-on-need-to-foster-fraternity-eschew-violence/2247394/

31 August, 2024 09:16 pm IST

New Delhi, Aug 31 (PTI) Manipur University collaborated with the NHRC for a two-day training programme on human rights in the strife-torn state, with a top official asserting that one should rely on “constitutional and legal provisions rather than violence” to achieve justice.

Bharat Lal, the National Human Rights Commission (NHRC) secretary general, during his valedictory address at the just-concluded programme, also said that “upholding human rights must be an internal commitment, not an externally imposed duty”.

The programme, hosted at the Court Hall of Manipur University, witnessed the participation of more than 100 legal experts, academics, human rights activists and students.

Clashes between the Kuki-zo and the Meiti ethnic groups in the state since May 2023 have left 226 dead, according to official records.

Lal in his address “stressed on the need to foster fraternity among people as enshrined in the Constitution, urging reliance on constitutional and legal provisions rather than violence to achieve justice”, according to a statement issued by the NHRC on Saturday.

He emphasised that the Preamble, the soul of the Constitution, encapsulated the core ideals of equality, justice, liberty, and fraternity.

Lal asserted that any form of violence was fundamentally a violation of human rights, highlighting that “war, terrorism, and violence are among the greatest threats to human life and dignity”.

He urged the students and teachers alike to actively promote peace and respect for human rights of all human beings, emphasising that these efforts were essential for securing prosperity and a bright future for the younger generation. PTI KND SZM

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

The Indian Awaaz

If 80 crore people can receive free food grains, rehabilitation of 4 lakh beggars should not be difficult task

https://theindianawaaz.com/if-80-crore-people-can-receive-free-food-grains-rehabilitation-of-4-lakh-beggars-should-not-be-difficult-task/

Aug 31, 2024

NHRC, India organizes an open house discussion on preventing beggary and rehabilitation of individuals engaged in beggary

Acting Chairperson, Smt. Vijaya Bharathi Sayani says, despite economic progress and several government initiatives, the continuing practice of begging indicates deep socio-economic disparities in the country

Secretary General, Bharat Lal says, if 80 crore people in the country can receive free food grains, rehabilitation of about 4 lakh individuals engaged in begging should not be difficult

Among various suggestions, mapping of areas of high concentration of beggars, issuing Aadhar cards to them and de-criminalisation of begging highlighted

Staff Reporter / New Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC), India Acting Chairperson, Smt. Vijaya Bharathi Sayani has said that despite rapid economic progress and several initiatives and welfare programmes implemented by both the Centre and State Governments, the continuing practice of begging indicates deep socio-economic disparities in the country.

She was speaking at an open house discussion on ‘Preventing beggary and rehabilitation of individuals engaged in beggary’ at its premises here on Friday August 30.

As per the 2011 census, there were more than 413 thousand beggars and vagrants in India. They include women, children, transgender and elderly who are forced to beg for survival.

She said that earlier, giving and accepting alms was part of spiritual practices aimed at cultivating humility but these days an act of charity has detached from its original intent and become begging either due to poverty or criminal activities even involving the trafficking of persons including children for this purpose generating a substantial amount of money for their captors. Further, as a result of societal neglect, physically challenged individuals have no choice but to depend on others for survival and daily sustenance.

Smt. Vijaya Bharathi Sayani said that the Commission is dedicated to protecting the human rights of these individuals, ensuring they are treated with dignity and fairness. In this context, she also highlighted the importance of the Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE)-B Scheme, which focuses on the rehabilitation of individuals engaged in begging.

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal said that recently, the Commission issued an Advisory to the Centre and State governments and UT Administrations to develop strategies aimed at eliminating the need for begging and enhancing the quality of life for those involved in it. He also said that governments, especially in recent years, have been committed to continually improving the quality of life for citizens. There have been focused efforts to ensure universal access to basic services such as water, housing, and electricity. He pointed out that if 80 crore people in the country can receive free food grains, rehabilitation of about 4 lakh individuals engaged in begging should not be difficult.

Shri Lal said that if different stakeholders including civil society organizations worked together it should not be difficult to rehabilitate them. They can also have access to food grains, housing, electricity connections, toilets, and cooking gas by providing an Aadhar card to them.

Earlier, giving an overview of the open discussion, Shri Devendra Kumar Nim, Joint Secretary emphasized the need to re-evaluate existing laws and approaches, advocating for a shift from punitive measures to a focus on rehabilitation, in alignment with constitutional principles and recent court rulings. This shift offers a path to more effective and humane solutions to the issue of begging.

Shri Rajesh Kumar, Director of the Society for Promotion of Youth & Masses said that his organization has nearly achieved 100 percent Aadhar Card enrollment for the residents of their shelter homes. Shri Chandra Mishra, Director of Beggars Corporation Private Limited, shared how he is transforming beggars into entrepreneurs by involving them as stakeholders in his company.

The other participants included Shri Joginder Singh, Registrar (Law), NHRC, representative of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of Bihar, Government of Rajasthan, Government of NCT of Delhi, NGOs, Academia, and eminent subject-matter experts.

Some of the key suggestions that emanated from the meeting include:

• Identify and map areas with high concentrations of begging, and conduct a survey of beggars to create a comprehensive database;

• State governments should work towards issuing Aadhaar cards to all beggars, facilitating their access to social security schemes and benefits;

• Begging should be decriminalized, as punitive measures and rehabilitation efforts cannot be effectively combined;

• Beggars are not a homogeneous group; therefore, initiatives for them should be tailored to meet their individual needs.

Northeast

Manipur University, NHRC organises 2-day training program on human rights in India

https://nenow.in/north-east-news/manipur-university-nhrc-organises-2-day-training-program-on-human-rights-in-india.html

August 31, 2024 9:22 pm

Guwahati: The Manipur University in collaboration with the National Human Rights Commission (NHRC) successfully concluded a two-day training programme on human rights in India.

The programme, hosted at the university's court hall, witnessed the participation of over 100 legal experts, academicians, human rights defenders and students.

The programme was concluded with the valedictory address delivered by Bharat Lal, Secretary General of the NHRC.

In his address, Lal emphasised the importance of the true meaning of preamble, fundamental rights and directive principles of state policy.

He also spoke on constitutional and legal recourse available to citizens for securing justice, especially Article 32 in seeking justice.

He reiterated the government's responsibility in upholding civil, political, cultural and socio-economic rights.

Lal stressed the need to foster fraternity among people as enshrined in the Constitution, urging reliance on constitutional and legal provisions rather than violence to achieve justice.

He asserted that upholding human rights must be an internal commitment, not an externally imposed duty.

Lal emphasised that the preamble, the soul of the Constitution, encapsulates the core ideals of equality, justice, liberty and fraternity.

He asserted that any form of violence is fundamentally a violation of human rights, highlighting that war, terrorism and violence are among the greatest threats to human life and dignity.

Lal urged the students and teachers alike to actively promote peace and respect for human rights of all human beings emphasising that these efforts are essential for securing prosperity and a bright future for the younger generation.

He also highlighted the NHRC's recent camp sitting in Guwahati, where 25 cases of alleged human rights violations in Manipur were addressed.

He reaffirmed the NHRC’s commitment to protecting and promoting human rights for all, calling for collective resolve and sustained efforts to ensure that respecting human rights becomes a way of life.

He concluded by encouraging partnerships to improve lives and ensure dignity for everyone.

The programme featured eight key sessions addressing critical aspects of human rights.

?The event brought together over 100 participants, including legal experts, academicians and human rights activists.

This programme marks a significant step in advancing human rights education and advocacy in the Northeast, with continued commitment from NHRC to fostering respect and understanding of human rights.

Latestly

India News | Manipur: NHRC Stresses on Need to Foster Fraternity, Eschew Violence

Get latest articles and stories on India at LatestLY. Manipur University collaborated with the NHRC for a two-day training programme on human rights in the strife-torn state, with a top official asserting that one should rely on "constitutional and legal provisions rather than violence" to achieve justice.

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-manipur-nhrc-stresses-on-need-to-foster-fraternity-eschew-violence-6230576.html

PTI | Aug 31, 2024 09:12 PM IST

New Delhi, Aug 31 (PTI) Manipur University collaborated with the NHRC for a two-day training programme on human rights in the strife-torn state, with a top official asserting that one should rely on "constitutional and legal provisions rather than violence" to achieve justice.

Bharat Lal, the National Human Rights Commission (NHRC) secretary general, during his valedictory address at the just-concluded programme, also said that "upholding human rights must be an internal commitment, not an externally imposed duty".

The programme, hosted at the Court Hall of Manipur University, witnessed the participation of more than 100 legal experts, academics, human rights activists and students.

Clashes between the Kuki-zo and the Meiti ethnic groups in the state since May 2023 have left 226 dead, according to official records.

Lal in his address "stressed on the need to foster fraternity among people as enshrined in the Constitution, urging reliance on constitutional and legal provisions rather than violence to achieve justice", according to a statement issued by the NHRC on Saturday.

He emphasised that the Preamble, the soul of the Constitution, encapsulated the core ideals of equality, justice, liberty, and fraternity.

Lal asserted that any form of violence was fundamentally a violation of human rights, highlighting that "war, terrorism, and violence are among the greatest threats to human life and dignity".

He urged the students and teachers alike to actively promote peace and respect for human rights of all human beings, emphasising that these efforts were essential for securing prosperity and a bright future for the younger generation.

(This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body)

Hindu

NHRC and Damodaram Sanjivayya National Law University host Open House discussion on fishermen's rights in Visakhapatnam

https://www.thehindu.com/news/cities/Visakhapatnam/nhrc-and-damodaram-sanjivayya-national-law-university-host-open-house-discussion-on-fishermens-rights-in-visakhapatnam/article68589538.ece

Published - August 31, 2024 07:07 pm IST - Visakhapatnam

The Hindu Bureau

National Human Rights Commission (NHRC), in collaboration with Damodaram Sanjivayya National Law University, Visakhapatnam, organised a one-day Open House discussion on 'Rights of Fishermen', on the university's auditorium here on Saturday.

NHRC acting Chairperson Vijaya Bharathi Sayani delivered the inaugural address and the university Vice-Chancellor D. Surya Prakasa Rao gave the welcome address.

Technical sessions on topics like Human Rights Violation in India's Fishing Communities, Fishing Rights & Environmental Issues, and Social Security Measures /Welfare Schemes for the Fishermen Community, were held.

The Centre's Fisheries Department Commissioner K. Mohammad Koya was present among others.

NE Now News

Manipur University, NHRC organises 2-day training program on human rights in India

https://nenow.in/north-east-news/manipur-university-nhrc-organises-2-day-training-program-on-human-rights-in-india.html

August 31, 2024 9:22 pm

Manipur University and NHRC organises 2-day training program on human rights in India

Guwahati: The Manipur University in collaboration with the National Human Rights Commission (NHRC) successfully concluded a two-day training programme on human rights in India.

The programme, hosted at the university's court hall, witnessed the participation of over 100 legal experts, academicians, human rights defenders and students.

The programme was concluded with the valedictory address delivered by Bharat Lal, Secretary General of the NHRC.

In his address, Lal emphasised the importance of the true meaning of preamble, fundamental rights and directive principles of state policy.

He also spoke on constitutional and legal recourse available to citizens for securing justice, especially Article 32 in seeking justice.

He reiterated the government's responsibility in upholding civil, political, cultural and socio-economic rights.

Lal stressed the need to foster fraternity among people as enshrined in the Constitution, urging reliance on constitutional and legal provisions rather than violence to achieve justice.

He asserted that upholding human rights must be an internal commitment, not an externally imposed duty.

Lal emphasised that the preamble, the soul of the Constitution, encapsulates the core ideals of equality, justice, liberty and fraternity.

He asserted that any form of violence is fundamentally a violation of human rights, highlighting that war, terrorism and violence are among the greatest threats to human life and dignity.

Lal urged the students and teachers alike to actively promote peace and respect for human rights of all human beings emphasising that these efforts are essential for securing prosperity and a bright future for the younger generation.

He also highlighted the NHRC’s recent camp sitting in Guwahati, where 25 cases of alleged human rights violations in Manipur were addressed.

He reaffirmed the NHRC’s commitment to protecting and promoting human rights for all, calling for collective resolve and sustained efforts to ensure that respecting human rights becomes a way of life.

He concluded by encouraging partnerships to improve lives and ensure dignity for everyone.

The programme featured eight key sessions addressing critical aspects of human rights.

?The event brought together over 100 participants, including legal experts, academicians and human rights activists.

This programme marks a significant step in advancing human rights education and advocacy in the Northeast, with continued commitment from NHRC to fostering respect and understanding of human rights.

Hindu

Kolkata doctor case highlights: “State government tried to create confusion, state police not coordinating with CBI,” says BJP’s Dilip Ghosh

Kolkata doctor rape and murder protest Highlights: Adhir Ranjan Choudhary alleges Kolkata police kept victims family under house arrest

The Joint Council of Doctors and the ‘Teachers for RG Kar’ staged protests against R.G. Kar Medical College rape and murder case, demanded punishment for the culprits and women’s security at workplaces

https://www.thehindu.com/news/national/west-bengal/kolkata-doctor-rape-and-murder-protest-live-august-31-2024/article68588624.ece

Updated - August 31, 2024 08:57 pm IST

Published - August 31, 2024 11:24 am IST

The Hindu Bureau

Ahead of the upcoming special session of the West Bengal Legislative Assembly, the Trinamool Congress has stepped up the campaign demanding capital punishment for those convicted of rape. The Assembly Session has been convened to pass legislation along similar lines.

The Calcutta High Court directed the the release of Paschim Banga Chhatra Samaj leader Sayan Lahiri and added that no coercive action can be taken against him.

The Federation of All India Medical Association (FAIMA) will hold a peaceful protest at Jantar Mantar in Delhi on Saturday, August 31, 2024 over the rape and murder of a trainee doctor at the R.G. Kar College and Hospital in Kolkata.

According to the statement issued by FAIMA, the protest aims to demand justice for the victim and press the government to expedite the enactment of the long-pending Central Healthcare Protection Act, which seeks to ensure the safety of healthcare professionals across the country.

Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Kolkata Police Commissioner over the alleged use of excessive and brutal force on August 27 on protesters, who were demonstrating to demand justice for the victim in the RG Kar Medical College rape-murder case.

Zee News

Bihar News: नीतीश सरकार को NHRC ने भेजा नोटिस, 48 घंटे के अंदर 63 मामलों का मांगा जवाब

NHRC News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के अधिकारियों पर गंभीर मामलों की फाइलें दबाने का आरोप लगाया है. आयोग ने गृह विभाग से इन मामलों की रिपोर्ट मांगी है.

https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/politics/bihar-nhrc-sent-notice-to-nitish-government-sought-response-on-63-cases-within-48-hours/2408690

Aug 31, 2024, 04:35 PM IST

NHRC Action On Bihar: बिहार में अपराध के गंभीर मामलों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्ती बरतते हुए प्रदेश सरकार से 48 घंटों के अंदर 63 मामलों की रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने कहा कि इन 63 मामलों की फाइलें अधिकारियों ने दबा रखी है. आयोग ने गृह विभाग को सभी जिलों की रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेवारी सौंपी है. इसके बाद गृह विभाग ने जिलों को रिपोर्ट के लिए 31 अगस्त का समय निर्धारित कर दिया है. इस पर संज्ञान लेते हुए गृह विभाग की विशेष शाखा के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है. सुहिता अनुपम ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज ये मामले बेहद गंभीर किस्म के हैं, जिनमें मुख्य सचिव से लेकिर जिला पदधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है.

सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को इसे 31 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और इसकी सूचना गृह विभाग को देने का निर्देश दिया है. इन मामलों में दरभंगा जिले में एक किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला भी शामिल है. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा था. NHRC ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से इस मामले में 6 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. इसके अलावा मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में भी पीड़ितों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें आयोग ने प्रशासन को दो-दो लाख रुपये की अंतरित सहायता देने का आदेश दिया गया था.

में अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में भी आयोग ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को नोटिस किया था. दरअसल, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिस जवान ने डंडा मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़ दी थी. पुलिस जवान द्वारा अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया था. NHRC ने सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर की पुलिस से पूछा था कि अधिवक्ता पर डंडा क्यों चलाया गया और अधिवक्ता की आंख क्यों फोड़ी गई?

Kranti Odisha News

एनएचआरसी, भारत ने भिक्षावृत्ति को रोकने और भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास पर एक खुली चर्चा आयोजित की

https://krantiodishanews.in/post/6072

August 31, 2024

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने नई दिल्ली में अपने परिसर में 'भिक्षावृत्ति की रोकथाम और भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास' पर एक खुली चर्चा आयोजित की। इसकी अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि तेजी से आर्थिक प्रगति और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई कई पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बावजूद भिक्षावृत्ति की प्रथा जारी रहना देश में गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 413 हज़ार से ज़्यादा भिखारी और आवारा लोग थे। इनमें महिलाएँ, बच्चे, ट्रांसजेंडर और बुज़ुर्ग शामिल हैं, जो जीवनयापन के लिए भीख माँगने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि पहले दान देना और लेना आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा था जिसका उद्देश्य विनम्रता विकसित करना था, लेकिन आजकल दान देना मूल उद्देश्य से अलग हो गया है और गरीबी या आपराधिक गतिविधियों के कारण भीख मांगना बन गया है, यहाँ तक कि इस उद्देश्य के लिए बच्चों सहित मानव दुर्व्यापर जैसी गतिविधियां भी शामिल है, जिससे उनके अपहरणकर्ताओं के लिए काफी मात्रा में धन कमाया जाता है। इसके अलावा, सामाजिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पास जीवित रहने और दैनिक भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि आयोग इन व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाए। इस संदर्भ में, उन्होंने आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल)-बी योजना के महत्व पर भी बात की, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास पर केंद्रित है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा कि हाल ही में, आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज क्षेत्रों के प्रशासनों को भिक्षावृत्ति को समाप्त करने और इसमें शामिल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीति विकसित करने के लिए एक परामर्शी जारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें, विशेष रूप से हाल के वर्षों में, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पानी, आवास और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल सकता है, तो भिक्षावृत्ति में लिप्त लगभग 4 लाख व्यक्तियों का पुनर्वास मुश्किल नहीं होना चाहिए।

श्री लाल ने कहा कि यदि नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारक मिलकर काम करें तो उनका पुनर्वास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन्हें आधार कार्ड उपलब्ध कराकर खाद्यान्न, आवास, बिजली कनेक्शन, शौचालय और रसोई गैस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

इससे पहले, खुली चर्चा का संक्षिप्त विवरण देते हुए, संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम ने मौजूदा कानूनों और दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया, संवैधानिक सिद्धांतों और हाल के न्यायालय के फैसलों के अनुरूप दंडात्मक उपायों से पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भिक्षावृत्ति की समस्या के लिए अधिक प्रभावी और मानवीय समाधानों का मार्ग प्रदान कर सकता है।

सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के निदेशक श्री राजेश कुमार ने कहा कि उनके संगठन ने अपने आश्रय गृहों के निवासियों के लिए लगभग 100 प्रतिशत आधार कार्ड नामांकन हासिल कर लिया है। बेगर्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री चंद्र मिश्रा ने बताया कि वे किस तरह से भिखारियों को अपनी कंपनी में हितधारक के रूप में शामिल करके उन्हें उद्यमी बना रहे हैं।

अन्य प्रतिभागियों में श्री जोगिंदर सिंह, रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार, गैर सरकारी संगठन, शिक्षाविद और प्रख्यात विषय-वस्तु विशेषज्ञ शामिल थे।

बैठक में सामने आए कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं

• भिखारियों की अधिकता वाले क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण करना, तथा व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए भिखारियों का सर्वेक्षण करना;

• राज्य सरकारों को सभी भिखारियों को आधार कार्ड जारी करने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुँच में आसानी हो;

• भिक्षावृत्ति को अपराध से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि दंडात्मक उपायों और पुनर्वास प्रयासों को प्रभावी ढंग से जोड़ा नहीं जा सकता;

• भिखारियों का समरूप समूह नहीं हैं; इसलिए, उनके लिए पहल उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जानी चाहिए।

Outlook Hindi

मणिपुर: एनएचआरसी ने भाईचारा बढ़ाने और हिंसा से बचने की जरूरत पर दिया जोर

मणिपुर विश्वविद्यालय ने संघर्षग्रस्त राज्य में मानवाधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के...

https://outlookhindi.com/country/general/manipur-nhrc-stresses-on-the-need-to-promote-brotherhood-and-avoid-violence-90253

AUG 31 , 2024

आउटलुक टीम

मणिपुर विश्वविद्यालय ने संघर्षग्रस्त राज्य में मानवाधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनएचआरसी के साथ सहयोग किया, जिसमें एक शीर्ष अधिकारी ने जोर देकर कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए "हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों" पर भरोसा करना चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने हाल ही में संपन्न कार्यक्रम में अपने समापन भाषण के दौरान यह भी कहा कि "मानवाधिकारों को बनाए रखना एक आंतरिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि बाहरी रूप से लगाया गया कर्तव्य"।

मणिपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 100 से अधिक कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मई 2023 से राज्य में कुकी-ज़ो और मैती जातीय समूहों के बीच संघर्ष में 226 लोग मारे गए हैं।

एनएचआरसी द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, लाल ने अपने संबोधन में "संविधान में निहित लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर भरोसा करने का आग्रह किया"। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल आदर्शों को समाहित करती है।

लाल ने जोर देकर कहा कि हिंसा का कोई भी रूप मूल रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "युद्ध, आतंकवाद और हिंसा मानव जीवन और सम्मान के लिए सबसे बड़े खतरों में से हैं"। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों के लिए शांति और सम्मान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि ये प्रयास युवा पीढ़ी के लिए समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।

The Print Hindi

मणिपुर: एनएचआरसी ने भाईचारा बढ़ाने और हिंसा से बचने की आवश्यकता पर बल दिया

https://hindi.theprint.in/india/manipur-nhrc-stresses-need-to-foster-brotherhood-and-avoid-violence/725024/

31 August, 2024 10:33 pm IST

नयी दिल्ली, 31 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया है कि न्याय प्राप्त करने के लिए “हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों” पर भरोसा किया जाना चाहिए।

मणिपुर विश्वविद्यालय ने हिंसाग्रस्त इस राज्य में एनएचआरसी के साथ मिलकर मानवाधिकारों पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

भरत लाल ने हाल ही में संपन्न कार्यक्रम में अपने समापन भाषण के दौरान यह भी कहा कि “मानवाधिकारों को अक्षुण्ण रखना आंतरिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि बाहरी तौर पर थोपा गया कर्तव्य”।

मणिपुर विश्वविद्यालय के ‘कोर्ट हॉल’ में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मई 2023 से राज्य में कुकी-जो और मेइती जातीय समूहों के बीच चले संघर्ष में 226 लोग मारे गए हैं।

एनएचआरसी की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, लाल ने अपने संबोधन में “संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर भरोसा करने का आग्रह किया”।

उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल आदर्शों को समाहित करती है।

लाल ने जोर देकर कहा कि हिंसा का कोई भी रूप मूल रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों के लिए शांति और सम्मान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया।

भाषा सुरेश प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Latestly

देश की खबरें | मणिपुर: एनएचआरसी ने भाईचारा बढ़ाने और हिंसा से बचने की आवश्यकता पर बल दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया है कि न्याय प्राप्त करने के लिए "हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों" पर भरोसा किया जाना चाहिए।

https://hindi.latestly.com/agency-news/manipur-nhrc-stresses-the-need-to-promote-brotherhood-and-avoid-violencer-2289309.html

Aug 31, 2024 10:28 PM IST

नयी दिल्ली, 31 अगस्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया है कि न्याय प्राप्त करने के लिए "हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों" पर भरोसा किया जाना चाहिए।

मणिपुर विश्वविद्यालय ने हिंसाग्रस्त इस राज्य में एनएचआरसी के साथ मिलकर मानवाधिकारों पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

भरत लाल ने हाल ही में संपन्न कार्यक्रम में अपने समापन भाषण के दौरान यह भी कहा कि "मानवाधिकारों को अक्षुण्ण रखना आंतरिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि बाहरी तौर पर थोपा गया कर्तव्य"।

मणिपुर विश्वविद्यालय के 'कोर्ट हॉल' में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मई 2023 से राज्य में कुकी-जो और मेइती जातीय समूहों के बीच चले संघर्ष में 226 लोग मारे गए हैं।

एनएचआरसी की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, लाल ने अपने संबोधन में "संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर भरोसा करने का आग्रह किया"।

उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल आदर्शों को समाहित करती है।

लाल ने जोर देकर कहा कि हिंसा का कोई भी रूप मूल रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों के लिए शांति और सम्मान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Janta Se Rishta

एनएचआरसी का मुख्य सचिव और दो जिलाधिकारियों को नोटिस

https://jantaserishta.com/local/odisha/nhrc-issues-notice-to-chief-secretary-and-two-district-magistrates-3496265

31 Aug 2024 10:37 AM

क्योंझर Keonjhar: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने याचिका में उल्लिखित घटनाओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सुबरनपुर और जिला मजिस्ट्रेट क्योंझर से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगी है। अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए, एनएचआरसी ने इस वर्ष 28 अगस्त को आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने ओडिशा के अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, आंगनवाड़ी और आवासीय घरों में सर्पदंश की विभिन्न घटनाओं और सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की विफलता का हवाला दिया है। याचिका में क्योंझर जिले के आनंदपुर में एक उपखंड अस्पताल में सर्पदंश की घटना का हवाला दिया गया है।

बाजू चंपिया (23) नामक व्यक्ति अस्पताल के बरामदे में सो रहा था क्योंकि उसकी मां डायरिया के इलाज के लिए अस्पताल में थी और उसे अस्पताल में ही सांप ने काट लिया। याचिका में सांप के काटने की एक और घटना का हवाला दिया गया है जिसमें क्योंझर जिले के आनंदपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत घटुआन गांव में चार महीने की बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी, जब वह अचानक रोने लगी और उसे सांप ने काट लिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। याचिका में एक और घटना का हवाला दिया गया है जो 24 जून को सुबरनपुर जिले के बिरमहाराजपुर पुलिस स्टेशन में हुई थी जब सांप बचाने वाले गौरा कुंभार की सांप के काटने से मौत हो गई थी, जबकि पुलिसकर्मी थाने के अंदर कुंभार द्वारा सांपों का खेल देखने में व्यस्त थे। सर्पदंश से संबंधित कई अनसुलझे मुद्दे उठाते हुए त्रिपाठी ने कहा कि सर्पदंश से लोगों की जान बचाने में सरकार की विफलता और लापरवाही के कारण पिछले आठ वर्षों में राज्य में 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

Navbharat News

एनएचआरसी ने प्रदर्शन के दौरान 'क्रूर बल' के इस्तेमाल को लेकर कोलकाता पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया

https://navabharat.news/nhrc-issues-notice-to-kolkata-police-chief-over-use-of-brute-force-during-protest/

August 31, 2024

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर 27 अगस्त को कथित रूप से अत्यधिक और क्रूर बल इस्तेमाल करने के मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस बृहस्पतिवार को भारतीय मानवाधिकार पहल के ओ पी व्यास की शिकायत के बाद जारी किया गया। अपनी शिकायत में व्यास ने आरोप लगाया है कि 27 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में न्याय की मांग को लेकर छात्रों द्वारा कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर "अत्यधिक और क्रूर बल का प्रयोग किया"।

शिकायत पर गौर करते हुए एनएचआरसी ने कहा है कि यदि आरोप सही हैं तो यह शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है।